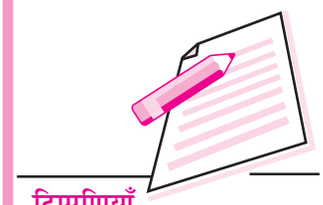

4

बेरोजगारी, निर्धनता और असमानता की समस्या

भारत में बेरोजगारी और निर्धनता आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं रही हैं। इस संदर्भ में प्रदेशीय विषमता भी महत्त्वपूर्ण है। आर्थिक सुधार, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और उपलब्ध संसाधनों के बदतर उपयोग से बेरोजगारी और निर्धनता की समस्या को कम करने की आशा की जा सकती है। सरकारी संस्थाओं द्वारा भी निर्धनता उन्मूलन के दीर्घकालिक उपाय प्रारंभ करने की आवश्यकता है। रोजगार सृजन के अवसर और आय के वितरण में असमानता ये दो प्रमुख कारक हैं, जो बेरोजगारी और निर्धनता की दोहरी समस्या को हल करने में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद आप:

- बेरोजगारी का अर्थ, प्रकार तथा उसे दूर करने के उपायों की व्याख्या कर पाएंगे;
- बेरोजगारी के कारणों को चिन्हित कर पाएंगे;
- निर्धनता उन्मूलन तथा रोजगार सृजन की सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों और कार्यक्रमों को जान पाएंगे; तथा
- भारत में प्रदेशीय विषमता की मात्रा तथा कारणों का मूल्यांकन कर पाएंगे।

4.1 भारत में बेरोजगारी की बड़ी मात्रा और माप

4.1.1 बेरोजगारी का अर्थ और उसके प्रकार

किसी देश की जनसंख्या के दो घटक होते हैं। (i) श्रम शक्ति तथा (ii) गैर-श्रम शक्ति। श्रम शक्ति से अभिप्राय उन सभी व्यक्तियों से है, जो कार्य कर रहे हैं (अर्थात् आर्थिक गतिविधि

में संलग्न है) तथा वे जो कार्य नहीं कर रहे हैं, किंतु वर्तमान मजदूरी की दर पर कार्य करने के लिए उपलब्ध है या कार्य की तलाश में हैं। इसका अभिप्राय है कि श्रम शक्ति में रोजगार युक्त तथा बेरोजगार व्यक्ति दोनों सम्मिलित होते हैं।

जनसंख्या का वह घटक, जो श्रम शक्ति का भाग नहीं है, गैर-श्रम शक्ति है। इसमें वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो कार्य नहीं कर रहे है और न ही कार्य की तलाश में हैं और न ही कार्य के लिए उपलब्ध हैं। बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है, जिसमें किसी कार्य करने के लिए इच्छुक तथा योग्य व्यक्ति को वर्तमान मजदूरी की दर पर कार्य उपलब्ध नहीं होता। यह एक प्रकार की अनैच्छिक बेरोजगारी है, ऐच्छिक बेरोजगारी नहीं। साधारण रूप से यह कह सकते हैं कि एक बेरोजगार व्यक्ति वह व्यक्ति है, जो श्रम शक्ति का क्रियाशील सदस्य है और रोजगार की तलाश में है, किंतु उसे पाने में असमर्थ है। ऐच्छिक बेरोजगारी के विषय में एक व्यक्ति अपने स्वयं के चुनाव के कारण बेरोजगार है। प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य नहीं करना चाहता या तो उसे अधिक मजदूरी चाहिए अथवा वह कार्य करना ही नहीं चाहता। दूसरी ओर अनैच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है, जबकि एक व्यक्ति लाभकारी कार्य से अलग है और वेतन प्राप्त नहीं करता, जबकि वह आय कमाने के योग्य है और उसे प्राप्त करने का इच्छुक है। बेरोजगारी में केवल अनैच्छिक बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी को आगे चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, संघर्षात्मक बेरोजगारी तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी में विभाजित किया जा सकता है।

4.1.1.1 चक्रीय बेरोजगारी

चक्रीय या मांग में कमी के कारण बेरोजगारी तब होती है, जब अर्थव्यवस्था को कम श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। जब वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग में संपूर्ण देश में कमी होती है, रोजगार कम हो जाता है और उसी के अनुसार बेरोजगारी में वृद्धि होती है। चक्रीय बेरोजगारी अवसाद अथवा मंदी में होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी व्यापक चक्रों के कारण होती है। उदाहरण के लिए, 2008 में वैश्विक मंदी के कारण विश्व में बहुत से श्रमिकों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा।

4.1.1.2 मौसमी बेरोजगारी

इस प्रकार की बेरोजगारी वर्ष में एक विशेष समय में अथवा मौसम में होती है और यह मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। मौसमी बेरोजगारी कृषि, पर्यटक, होटल, भोजन का प्रबंध करने जैसे उद्योगों में आमतौर से पाई जाती है।

4.1.1.3 संरचनात्क बेरोजगारी

संरचनात्मक बेरोजगारी उस समय होती है, जबकि किसी व्यक्ति की योग्यता उसके कार्य की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह मांग के स्वरूप में दीर्घकालीन परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है तथा अर्थव्यवस्था की मौलिक संरचना को परिवर्तित कर देती है। व्यक्ति नए विस्तृत आर्थिक क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली नई प्रौद्योगिकी को सीखने में असमर्थ रहता है।

इस प्रकार वे स्थायी रूप से बेरोजगार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कम्प्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ, बहुत से श्रमिकों को निकाल दिया गया। रोजगार की आवश्यकता और श्रमिकों के विद्यमान कौशल में तालमेल नहीं हो सकता था। यद्यपि रोजगार उपलब्ध थे, किंतु नए प्रकार के कौशल और योग्यता की आवश्यकता थी। इसलिए पुराने कौशल वाले व्यक्तियों को बदले हुए आर्थिक वातावरण में रोजगोर नहीं मिला और वे बेरोजगार हो गए।

4.1.1.4 संघर्षात्मक बेरोजगारी

संघर्षात्मक बेरोजगारी उस समय होती है, जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है। इसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं, जैसे–अच्छे रोजगार की तलाश, वर्तमान रोजगार से निकाले जाने पर, अपनी इच्छा से वर्तमान रोजगार छोड़ने पर। दूसरे रोजगार को प्राप्त करने में व्यक्ति को कुछ समय लग जाता है। उस समय अवधि में वह संघर्षात्मक रूप से बेरोजगार होता है।

4.1.1.5 प्राकृतिक बेरोजगारी की दर

संघर्षात्मक तथा संरचनात्मक बेरोजगारी के योग को बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं।

4.1.1.6 प्रच्छन्न बेरोजगारी

बेरोजगारी जो प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई दे, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। यह उस समय होती है, जबकि कोई व्यक्ति उत्पादन में कोई योगदान नहीं देता, जबकि प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता हुआ दिखाई देता है। माना किसी परिवार में 8 सदस्य हैं: सभी कृषि में लगे हैं। यदि दो सदस्य कृषि कार्य को छोड़कर दूसरा काम करने लग जाएं और वहां उन्हें आय प्राप्त हो। लेकिन उनकी कृषि का उत्पादन अब भी उतना ही हो रहा है जितना पहले होता था जब वे कृषि काम में लगे थे। इसका अर्थ यह हुआ कि वे बेरोजगार थे यद्यपि काम कर रहे थे। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। यह विशेष रूप से कृषि में होती है, जहां कृषक के पारिवारिक सदस्य भूमि पर कार्य करने में संलग्न तो होते हैं, किंतु दिए हुए उत्पादन के स्तर में कोई योगदान नहीं देते। इस प्रकार, उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है।

4.1.1.7 अल्प बेरोजगार

कभी-कभी एक व्यक्ति किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न तो है, परंतु वह उसे उसकी योग्यता और प्रयास के अनुसार पूर्ण रोजगार नहीं दे पाती। इस प्रकार यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें कोई व्यक्ति रोजगार युक्त होता है किंतु इच्छित क्षमता के अनुरूप नहीं, या मुआवजे, कार्य के घंटे, कौशल का स्तर और अनुभव के अनुसार नहीं। तकनीकी रूप से बेरोजगार न होते हुए भी अल्प बेरोजगारी, प्राय: उपलब्ध रोजगार के लिए प्रतियोगिता करता है।

4.2 बेरोजगारी का माप

बेरोजगारी की दर श्रम शक्ति का वह प्रतिशत है, जो बिना कार्य के है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है–

बेरोजगारी की दर = बेरोजगार श्रमिक/कुल श्रम शक्ति × 100

बेरोजगारी का माप एक कठिन कार्य है। भारत में रोजगार व बेरोजगारी पर सबसे अधिक विस्तृत और विश्वसनीय आंकड़े राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा संकलित किए जाते हैं। भिन्न-भिन्न अवधियों पर आधारित जैसे–एक वर्ष, एक सप्ताह, तथा सप्ताह के प्रत्येक दिन राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण संगठन रोजगार व बेरोजगारी के चार विभिन्न चार माप उपलब्ध कराता है। बेरोजगारी को मापने की कुछ विधियां निम्नलिखित हैं–

(i) सामान्य प्रमुख अवस्था बेरोजगारी (UPS)

इसको उन व्यक्तियों की संख्या के आधार पर मापा जाता है, जो वर्ष के प्रमुख भाग में बेरोजगार रहें। इस सर्वेक्षण में शामिल व्यक्तियों का वर्गीकरण उन व्यक्तियों में किया जाता है, जो कार्य कर रहे हैं और अथवा अपनी मुख्य क्रिया में कार्य के लिए उपलब्ध है और वे व्यक्ति, जो कार्य कर रहे हैं अथवा किसी सहायक क्रिया में कार्य के लिए उपलब्ध हैं अर्थात् एक क्षेत्र, जो उनकी मुख्य क्रिया से दूसरा है। इसलिए सामान्य अवस्था की अवधारणा के अंतर्गत अब अनुमान सामान्य मुख्य अवस्था तथा सामान्य मुख्य अवस्था व सहायक सामान्य अवस्था के आधार पर लगाए जाते हैं। सामान्य अवस्था बेरोजगार दर एक व्यक्तिगत दर है और स्थायी बेरोजगारी को बताती है, क्योंकि वे सभी जो निर्देषित वर्ष में सामान्य रूप से बेरोजगार पाए जाते हैं, उनकी गणना बेरोजगारों में की जाती है। यह माप उनके लिए अधिक उपयुक्त है, जो नियमित रोजगार की तलाश में होते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षित व कुशल व्यक्ति, जो आकस्मिक कार्य स्वीकार नहीं करते। इसे खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है।

(ii) सामान्य प्रमुख तथा सहायक अवस्था बेरोजगारी (UPSS)

यहां वह व्यक्ति बेरोजगार समझा जाता है, जो सामान्य प्रमुख अवस्था के अलावा सहायक कार्यों के लिए उपलब्धता है, किंतु किसी वर्ष में कार्य पाने में असमर्थ होते हैं।

(iii) वर्तमान साप्ताहिक अवस्था बेरोजगारी (CWS)

इससे तात्पर्य उन व्यक्तियों की संख्या से हैं, जिन्हें सर्वेक्षण सप्ताह मे एक घंटे का कार्य भी नहीं मिलता।

(iv) वर्तमान दैनिक अवस्था बेरोजगारी (CDS)

इससे तात्पर्य उन व्यक्तियों की संख्या से है, जिन्हें सर्वेक्षण सप्ताह में एक दिन या किसी दिन भी रोजगार नहीं मिलता।

विभिन्न अवधारणाओं पर आधारित बेरोजगारी की दरों में अंतर होता है।

सामान्य प्रमुख अवस्था तथा सामान्य प्रमुख तथा सहायक अवस्था के माप दीर्घकालीन बेरोजगारी को दर्शाते हैं। वर्तमान साप्ताहिक अवस्था का माप अल्पकालीन अवधि की बेरोजगारी को दर्शाता है, किंतु एक सप्ताह से कम बेरोजगारी को अनदेखा कर देता है। वर्तमान दैनिक अवस्था का माप खुली और आंशिक बेरोजगारी दोनों को दर्शाता है। विभिन्न मापों पर आधारित बेरोजगारी की दर नीचे तालिका 14.1 में दी गई है।

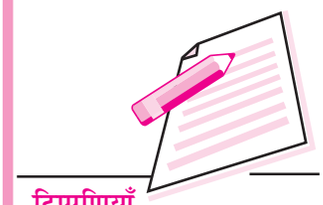

सारणी 4.1 : बेरोजगारी दर (प्रतिशत में)

वर्ष	2004-05	2009-10	2010-11
सामान्य प्रमुख तथा सहायक अवस्था	2.3	2.0	2.2
वर्तमान साप्ताहिक अवस्था	4.4	3.6	3.7
वर्तमान दैनिक अवस्था	8.2	6.6	5.6

स्रोत : राष्ट्रीय निदर्ष सर्वेक्षण संगठन, 2014 तक के सर्वेक्षण

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि 2004-05 के पश्चात् बेरोजगारी की दर में गिरावट हुई है। सामान्य प्रमुख तथा सहायक अवस्था 2004-05 से 2010-11 के बीच लगभग एक जैसी रही, 2 प्रतिशत से थोड़ी-सी अधिक, पर वर्तमान साप्ताहिक अवस्था 2004-05 में 4. 4 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में 3.6 प्रतिशत हो गई तथा 2010-11 लगभग उतनी ही 3.7 प्रतिशत रही। वर्तमान दैनिक अवस्था लगातार घटी। 2004-05 की तुलना में 2009-10 में बेरोजगारी 8.2 प्रतिशत से घटकर 6.6 प्रतिशत हो गई और 2010-11 से घटकर 5.6 प्रतिशत हो गई।

4.3 भारत में बेरोजगारी के कारण

4.3.1 धीमी आर्थिक संवृद्धि

आयोजन काल में संवृद्धि दर का झुकाव लक्ष्य दर से काफी कम था। इसलिए, पर्याप्त मात्रा में रोजगार का सृजन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त आर्थिक संवृद्धि स्वयं बेरोजगार की समस्या को हल नहीं करती। हाल के कुछ वर्षों में आर्थिक संवृद्धि में वृद्धि होते हुए भी रोजगार संवृद्धि में गिरावट आई है। इसकी व्याख्या के लिए, निर्माण कार्य के अलावा आर्थिक गतिविधि के प्रमुख क्षेत्रकों में उत्पादन में परिवर्तन के साथ रोजगार की मात्रा में लगातार गिरावट हुई है। टी.एस. पपोला के अनुसार, कुछ समय अवधि में कृषि और विनिर्माण क्षेत्रकों में उत्पादन वृद्धि तकनीक गहन अधिक तथा श्रम गहन कम रही है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रकों की संवृद्धि की बनावट भी बेरोजगारी की मुख्य निर्धारक है। कृषि पर अधिक निर्भरता तथा गैर-कृषि गतिविधियों की धीमी संवृद्धि रोजगार सृजन को सीमित करती है।

4.3.2 श्रम शक्ति में वृद्धि

श्रम शक्ति में वृद्धि लाने वाले दो महत्त्वपूर्ण कारक हैं, जो निम्नलिखित हैं–

(i) जनसंख्या में तीव्र वृद्धि : बढ़ती हुई जनसंख्या श्रम की पूर्ति में वृद्धि का कारण हुई हैं तथा बढ़ती हुई श्रम शक्ति के अनुसार, रोजगार अवसरों में वृद्धि न होने के कारण बेरोजगारी की समस्या और अधिक बढ़ गई है।

(ii) सामाजिक कारक : स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्रियों की शिक्षा ने रोजगार के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया है। उनमें से बहुत-सी, अब श्रम बाजार में रोजगार के लिए पुरुषों के साथ प्रतियोगिता करती हैं। किंतु अर्थव्यवस्था इन चुनौतियों का सामना करने में असफल रही है और इसका शुद्ध परिणाम यह है स्थाई बेरोजगारी में लगातार वृद्धि हुई है।

4.3.3 ग्रामीण-शहरी प्रवासन

शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारी मुख्य रूप से काफी मात्रा में ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों को पलायन के कारण हुई है। ग्रामीण क्षेत्र कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों में जीविकोपार्जन देने में असमर्थ रहे हैं, इसलिए शहरों के लिए बड़े पैमानों पर प्रवासन हो रहा है। शहरों में आर्थिक विकास नए आने वाले श्रमिकों को काफी अतिरिक्त रोजगार देने में असफल रहा है। इस प्रकार, केवल कुछ ही शहरों में आने वाले, उत्पादन गतिविधियों में लग पाते हैं तथा शेष बेरोजगारों की फौज में वृद्धि करते हैं।

4.3.4 अनुपयुक्त तकनीक

भारत में, यद्यपि पूँजी का अभाव है, श्रम अधिक मात्रा में उपलब्ध है फिर भी उत्पादक श्रम के स्थान पर पूँजी का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। इस नीति के परिणामस्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। श्रम की अधिकता होने पर भी, भारत में पूँजी-गहन तकनीक को अपनाया जा रहा है, क्योंकि श्रम के नियम कठोर हैं। आसानी से काम पर लगाना तथा आसानी से हटाने की नीति को अपनाना बहुत कठिन है। इसलिए, उद्योगों में श्रमिकों की उचित मात्रा का प्रयोग कठिन है। श्रम शक्ति को घटाना कठिन है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों में अशांति तथा काम करने के उचित आचरण में कमी आदि से श्रम की कार्य कुशलता में कमी आई है। जिससे संस्थानों द्वारा श्रम बचाओं तकनीकी के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है। परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ी है।

4.3.5 दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली

वर्तमान शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक आधारित है और व्यावहारिक उद्देश्य के लिए इसमें सीमित उपयोगिता है। यह कौशल और तकनीकी योग्यता पर बल नहीं देती, जिसकी आवश्यकता विभिन्न कार्यों में रोजगार की तलाश के लिए है। इससे कौशल और शिक्षण की आवश्यकता तथा उपलब्धता में असंतुलन उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण विशेष रूप से युवक और शिक्षित लोगों में बेरोजगारी बढ़ गई है। जबकि तकनीकी और विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की कमी जारी है।

4.3.6 आधारिक संरचना के विकास में कमी

निवेश तथा आधारिक संरचना के विकास की कमी विभिन्न क्षेत्रकों की संवृद्धि तथा उत्पादन क्षमता को सीमित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं होता है।

4.3.7 रोजगार की योग्यता में कमी

भारत को खराब स्वास्थ्य तथा पोषण की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे लोगों की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और यह बेरोजगारी का कारण बनती है।

पाठगत प्रश्न 4.1

1. बेरोजगारी दर क्या है? भारत में इसे कैसे मापा जाता है?

2. भारत में श्रम शक्ति में वृद्धि के क्या कारण हैं?

4.4 भारत में निर्धनता

सामान्य रूप से निर्धनता को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें लोग अपनी मौलिक आवश्यकताओं को भी संतुष्ट करने में असमर्थ होते हैं। निर्धनता की परिभाषा और मापने की विधियों में विभिन्न देशों में अंतर होता है। भारत में निर्धनता की मात्रा को, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर मापा जाता है।

4.4.1 निर्धनता रेखा

निर्धनता रेखा परिवार की आय को परिभाषित करती है। जिन परिवारों की आय इससे कम होती है, उन्हें निर्धन माना जाता है। विभिन्न देशों में एक परिवार की आय को परिभाषित करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। यह स्थानीय सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। भारत में निर्धनता के अनुमान योजना आयोग द्वारा लगाए जाते हैं।

निर्धनता, राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षणों द्वारा उपभोक्ता व्यय के आधार पर मापी जाती है। एक निर्धन परिवार वह है, जिसका व्यय एक विशेष निर्धनता रेखा के स्तर से कम होता है।

भारत में, पहले गरीबी रेखा को, 1979 में नियत कार्य शक्ति की विधि के आधार पर परिभाषित किया जताता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी का भोजन खरीदने पर व्यय तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी का भोजन खरीदने पर किए गए व्यय पर आधारित था। 2009 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने निर्धनता रेखा को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन पर व्यय के आधार पर परिभाषित किया।

योजना आयोग ने तेंदुलकर कमेटी की सिफारिश के अनुसार, निर्धनता रेखा तथा निर्धनता अनुपात को वर्ष 2009–10 के लिए परिष्कृत कर दिया है। इसने निर्धनता रेखा का अनुमान संपूर्ण भारत के स्तर पर लगाया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय 673 रु. तथा शहरी क्षेत्रों में 860 रु. है। इसलिए कोई व्यक्ति, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 673 रु. तथा शहरी क्षेत्रों में 860 रु. प्रति माह व्यय करता है, उसे निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाला परिभाषित किया जाता है।

इन सीमाओं के आधार पर भारत में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 2004-05 में 37.2 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में 29.8 प्रतिशत हो गया। निरपेक्ष रूप में भी निर्धन लोगों की संख्या इस अवधि में घटकर 52.4 मिलियन रह गई है। इसमें 48.1 मिलियन ग्रामीण निर्धन हैं तथा 4.3 मिलियन शहरी निर्धन हैं। इस प्रकार निर्धनता, 2004-05 से 2009-10 की अवधि में 1.5% दर प्रतिवर्ष कम हुई है। 1993-4 से 2004-5 की तुलना में 2004-5 से 2009-10 में गरीबी में दो गुनी कमी आई है।

सारणी 4.2 : निर्धनता अनुपात (संख्या प्रतिशत में)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	योग
1993-94	50.1	31	45.3
2004-05	41.8	25.7	37.2
2009-10	33	20.9	29.8

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2013

4.5 भारत में निर्धनता के कारण

4.5.1 गरीबी का दुष्चक्र

यह कहा जाता है कि 'एक देश निर्धन है, क्योंकि वह निर्धन है'। यह विचार रैगनर नर्सकी द्वारा दिया गया है, जिसने गरीबी के दुष्चक्र की समस्या को उजागर किया। बचत का नीचा स्तर निवेश की सीमा को घटाता है। निवेश का नीचा स्तर कम आय पैदा करता है। इस प्रकार निर्धनता का चक्र अनिश्चित काल तक चलता रहता है।

4.5.2 नीची प्राकृतिक संसाधन क्षमता

एक परिवार निर्धन होता है, यदि उसके अधिकार में आय कमाने वाली परिसंपत्तियों का योग, जिसमें भूमि, पूँजी तथा विभिन्न स्तरों के कौशल का श्रम निर्धनता रेखा से अधिक आय उपलब्ध नहीं करा सकता। गरीब के पास मुख्य रूप से अकुशल श्रम होता है, जिसे मजदूरी आय का उच्च स्तर नहीं प्राप्त होता।

4.5.3 आय और परिसंपत्तियों के वितरण में असमानता

आय और परिसंपत्तियों का वितरण भी आय के स्तर को निर्धारित करता है। आर्थिक असमानताएं, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण हैं। इसका अर्थ है कि संवृद्धि के लाभों का केन्द्रीयकरण हो गया है और निम्न आय वर्ग के उपभोग में सुधार नहीं हो पाया परिणामस्वरूप वह विकास के लाभ से वंचित रहा है।

4.5.4 सामाजिक सेवाओं तक पहुंच का अभाव

सामाजिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा तक जन साधारण की पहुंच का अभाव, भौतिक और मानवीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व में असमानता, समस्याओं को बढ़ा देते हैं। ये सेवाएं परिवारों

के कल्याण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। निर्धन व्यक्ति इन सेवाओं का उचित लाभ बहुत कम प्राप्त कर पाता है। यह आंशिक रूप से इसलिए है, क्योंकि सरकारें इस सेवाओं की पर्याप्त पूर्ति के लिए काफी निवेश नहीं करती और सीमित पूर्ति का लाभ मुख्य रूप से गैर-गरीब परिवारों द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्धन, बहुत से अन्य कारणों से भी, इनकी काफी पहुंच नहीं रखते, जैसे इन सेवाओं के उपलब्ध होने की सूचना का अभाव, ज्ञान का अभाव तथा सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार।

4.5.5 संस्थागत साख तक पहुंच का अभाव

बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं निर्धन लोगों को ऋण देने में पक्षपात करती हैं, क्योंकि उन्हें ऋण का भुगतान प्राप्त न होने का डर होता है। इसके अतिरिक्त जमानत के विषय में नियम, दस्तावेज की गवाही आदि निर्धन लोगों के लिए बैंक से ऋण लेने में रुकावट डालते हैं। संस्थागत ऋण पहुंच के बाहर होने के कारण निर्धन लोगों को भू-स्वामी तथा अन्य अनियमित स्रोतों से बहुत ऊंची ब्याज की दर पर ऋण लेने के लिए दबाव डालते हैं, जिससे उनकी दशा अन्य क्षेत्रों में कमजोर हो जाती है। उदाहरण के लिए, उन्हें भूमि के लिए लगान का ऊंचा भाग देना पड़ता है तथा बहुत प्रकार के बंधक मजदूरी के रूप में बहुत कम मजदूरी स्वीकार करनी पड़ती है अथवा उन्हें अपनी फसल बहुत नीची कीमत पर बेचनी पड़ती है। कुछ मामलों में निर्धन व्यक्ति अपने आपको इन ऋणदाताओं के पंजों से मुक्त नहीं करा पाते। ऋणग्रस्तता के कारण उनकी निर्धनता और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे ऋणी परिवार पीढ़ियों तक निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं, क्योंकि वे ऋण के जाल में फंस जाते हैं।

4.5.6 कीमत वृद्धि

बढ़ती हुई कीमतों से मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई है और इस प्रकार मुद्रा आय का वास्तविक मूल्य घट गया है। निम्न आय वर्ग के लोगों को विवश होकर अपना उपभोग कम करना पड़ता है और इस प्रकार वे निर्धनता रेखा से नीचे चले जाते हैं।

4.5.7 उत्पादक रोजगार का अभाव

निर्धनता की अधिक मात्रा का बेरोजगारी की दशा से सीधा संबंध है। वर्तमान रोजगार की दशाएं, निर्धनता के कारण एवं उचित रहन-सहन के स्तर की अनुमति नहीं देतीं। उत्पादन रोजगार का अभाव मुख्य रूप से आधारिक संरचना, आगत, साख, तकनीकी, बाजार की सहायता की समस्याओं के कारण हैं। प्रणाली में लाभदायक रोजगार के अवसरों का अभाव है।

4.5.8 तीव्र जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि का अर्थ है–सकल घरेलू उत्पाद में धीमी वृद्धि और इसलिए रहन-सहन के औसत स्तर में धीमा सुधार होता है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में बढ़ती हुई वृद्धि से उपभोग बढ़ता है तथा राष्ट्रीय बचत कम होती है, जिससे पूँजी निर्माण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि सीमित हो जाती है।

4.5.9 कृषि में नीची उत्पादकता

खेतों के छोटे-छोटे और बिखरे हुए होने, पूँजी का अभाव, कृषि की परंपरागत विधियों का प्रयोग, अशिक्षा आदि के कारण, कृषि में उत्पादन का स्तर नीचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का यह मुख्य कारण है।

4.5.10 सामाजिक कारण

(क) शिक्षा :

शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक एजेंट है। निर्धनता शिक्षा के स्तर से भी घनिष्ट रूप से संबंधित है और इन दोनों में चक्रीय संबंध है। कमाने की शक्ति व्यक्ति की शिक्षा और प्रतिशत में निवेश से प्रभावित होती है। किंतु निर्धन लोगों के पास मानव पूँजी निवेश के लिए निधि नहीं होती और इस प्रकार इससे उनकी आय सीमित होती है।

(ख) जाति प्रथा :

भारत में, जाति प्रथा, ग्रामीण निर्धनता के लिए सर्वदा उत्तरदायी रही है। नीची जाति के लोगों में ऊंची जाति के लोगों का वर्चस्व पहले की निर्धनता का कारण रही है। जाति प्रथा की दृढ़ता के कारण, नीची जाति के लोग बहुत-सी आर्थिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सके और वे निर्धन रहे।

(ग) सामाजिक प्रथाएं :

ग्रामीण लोग प्राय: अपनी कमाई का अधिक प्रतिशत सामाजिक प्रथाओं, जैसे–शादी, मृत्यु भोज आदि पर व्यय करते हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक ऋण लेते हैं। परिणामस्वरूप वे ऋण तथा निर्धनता में रहते हैं।

4.6 भारत में निर्धनता उन्मूलन तथा रोजगार सृजन के कार्यक्रम

सरकार सम्मिलित विकास प्राप्त करने के लिए, निर्धनता उन्मूलन तथा रोजगार सृजन की कुछ विशेष योजनाओं के माध्यम से ध्यान केंद्रित कर रही है।

4.6.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटो योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.)

सरकार के इस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है। प्रत्येक परिवार का कोई वयस्क सदस्य, जो अकुशल कार्य करना चाहता है, एक वर्ष में कम-से-कम 100 दिन का वेतन रोजगार गारंटी से प्राप्त कर सकता है। इसमें एक-तिहाई भाग स्त्रियों का होगा। यह योजना वेतन रोजगार उपलब्ध कराती है तथा कार्य के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को दृढ़ करती है और इसका उद्देश्य दीर्घकालीन निर्धनता जैसे–सूखा, वनों का काटना और भूमि के कटाव के कारणों को दूर करना है तथा इस प्रकार धारणीय विकास को प्रोत्साहन देना है।

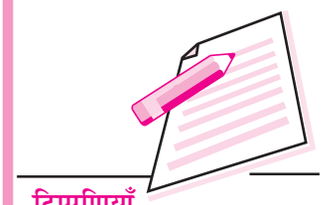

4.6.2 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। इसकी स्थापना अप्रैल, 1999 में की गई। इसका उद्देश्य सहायता दिए गए ग्रामीण निर्धन परिवारों को (स्वरोजगारियों/ बैंक ऋण तथा सरकारी आर्थिक सहायता के मिले-जुले माध्यम से आय सृजन की परिसंपत्तियां उपलब्ध कराकर, निर्धनता रेखा से ऊपर उठाना है। ग्रामीण निर्धनों को स्वयं सहायता वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है और उनकी क्षमता का निर्माण प्रशिक्षण और कौशल के विकास के माध्यम से किया जाता है।

4.6.3 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

यह योजना 1 दिसंबर, 1997 में लागू की गई। इसका उद्देश्य शहरी बेरोजगार या अल्प रोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार, साहसिक कार्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देकर अथवा वेतन रोजगार के अवसर प्रदान करके लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना है।

पाठगत प्रश्न 4.2

1. भारत में निर्धनता रेखा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

2. संस्थागत साख की उपलब्धता, भारत में निर्धनता के स्तर को कैसे प्रभावित करती है?

3. निर्धनता के दुष्चक्र से आपका क्या अभिप्राय है?

4.7 भारत में असमानता

भारत, काफी प्रभावशाली आर्थिक संवृद्धि वाला एक गतिशील देश है। विकास कार्यों के परिणाम स्वरूप यहां आर्थिक संवृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में सुधार, देश में निर्धनता के स्तर आदि में कमी आई है। यह वास्तविकता है कि देश की जनसंख्या में निर्धनों के प्रतिशत में लगातार कमी आई है। लेकिन देश के विभिन्न प्रांतों में सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। रहन-सहन के स्तर में भारी अंतर का विस्तार जिसे प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है। विभिन्न राज्यों में, प्रति व्यक्ति आय में अन्तर है जैसे बिहार में प्रतिव्यक्ति 12,000 रु. और गोवा में 100,000 रु. प्रति व्यक्ति आय है। ये इतिहास और भूतकालीन संवृद्धि के अनुभव के परिणाम हैं है। दूसरी अन्य संबंधित विषमताएं शिक्षा, साक्षरता दर, स्वास्थ्य, आधारिक संरचना, जनसंख्या वृद्धि, निवेश व्यय तथा प्रदेशों की बनावट में भी हैं। पिछले दशक में क्षेत्रीय विषमता दर्शाती है कि धनी और गरीब क्षेत्रों में काफी अंतर है, जिसमें गोवा सबसे अधिक धनी क्षेत्र है तथा बिहार सबसे गरीब क्षेत्र है। 2010-11 में चंडीगढ़ सबसे धनी था, किंतु बिहार सबसे गरीब रहा। इस अवधि में वार्षिक औसत वृद्धि दर में भी काफी अंतर हैं, जो चंडीगढ़ में 8.39 प्रतिशत है तथा जम्मू और कश्मीर में मात्र 2.71 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त इस दशक में ऊपर के चार सबसे धनी क्षेत्र अर्थात् गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडुचेरी में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू राज्य उत्पाद में दूसरे क्षेत्रों से काफी तीव्र गति से वृद्धि हुई है।

4.8 भारत में क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि के कारण

4.8.1 ऐतिहासिक कारक

भारत में ऐतिहासिक क्षेत्रीय असंतुलन अंग्रेजी शासन काल से प्रारंभ हुआ। अंग्रेज उद्योगपति अपनी आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से दो राज्यों– पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में केंद्रित रखते थे। प्रमुख रूप से उनके महानगरों जैसे–कोलकाता, मुंबई और चैन्नई में। उन्होंने अपने समस्त उद्योग इन नगरों में तथा उनके आस-पास केंद्रित किए तथा शेष देश को पिछड़ा रहने के लिए तिरस्कृत कर दिया।

4.8.2 भौगोलिक कारक

भारत का बड़ा भू-भाग, पहाड़ियों, नदियों तथा घने जंगलों से घिरा है। यह संसाधनों की गतिशीलता को आंशिक रूप से कठिन बनाने के अलावा विकसित योजनाओं की लागत तथा प्रशासन की लागत को बढ़ा देता है। प्रतिकूल जलवायु, बाढ़ आदि भी देश के विभिन्न क्षेत्रों के धीमे आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी कारक रहे हैं, जो कृषि की निम्न उत्पादकता तथा औद्योगीकरण के अभाव में दिखाई देते हैं। इन कारकों के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में असमान संवृद्धि हुई है।

4.8.3 आधारिक संरचना

जो राज्य अच्छी तरह विकसित हैं या जहां आधारिक संरचना जैसे शक्ति के साधन, जल, सड़कें और हवाई अड्डे हैं वे बड़ी निवेश योजनाओं को आकर्षित करते हैं तथा उनमें संवृद्धि की दर ऊंची होती है। मौलिक आधारिक संरचना के अभाव वाले गरीब राज्य निजी निवेश को आकर्षित करने में असफल रहते हैं। इससे आय के वितरण में असमानता तथा आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण की समस्या में वृद्धि हुई है।

4.8.4 सार्वजनिक निवेश में गिरावट

नई आर्थिक नीति में सरकार लगातार आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के संबंध में अपनी भूमिका सीमित कर रही है और निजी क्षेत्र को अधिक स्थान दे दिया गया हे। सार्वजनिक निवेश में लगातार गिरावट आई है। इसका निर्धन राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सिंचाई, बिजली तथा सामाजिक क्षेत्र योजनाओं में बहुत अधिक निवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र का इन राज्यों की संवृद्धि में मुख्य योगदान रहा है। इसमें गिरावट का बहुत से क्षेत्रों का विकास प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

पाठगत प्रश्न 4.3

1. श्रम शक्ति का प्रतिशत, जो बेरोजगार है, कहलाता है–

   (अ) रोजगार दर (ब) बेरोजगार जनसंख्या अनुपात

   (स) बेरोजगार दर (द) श्रम शक्ति दर

2. श्रम शक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है–

(अ) वे श्रमिक, जो कार्य की तलाश कर रहे हैं तथा प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य के लिए उपलब्ध है।

(ब) कोई जो कार्य कर रहा है अथवा सक्रिय रूप से कार्य की तलाश में है।

(स) स्कूल छोड़ने की आयु तथा सेवा निवृत्ति की आयु के बीच बड़ी जनसंख्या।

(द) वे जो यदि बेरोजगार रहते हैं तो लाभ प्राप्त करने का दावा करते हैं।

3. चक्रीय बेरोजगारी है–

(अ) बेरोजगारी, जिसके परिणामस्वरूप लोग रोजगार प्राप्त करने के अवसर के लिए हतोत्साहित हो जाते हैं और वे रोजगार की तलाश बंद कर देते हैं।

(ब) बेरोजगार, जो अवसाद और मंदी के समय उत्पन्न होता है।

(स) बेरोजगार का वह भाग, जो श्रम बाजार की सामान्य क्रिया के कारण होता है।

(द) बेरोजगार का वह भाग, जो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है तथा जिसके कारण कुछ उद्योगों में काफी मात्रा में रोजगार की हानि हो जाती है।

4. निम्न में भारत में निर्धनता रेखा मापने की विधि कौन-सी है?

(अ) निवेश पूँजी

(ब) पूँजी विधि

(स) मानव विधि

(द) आय विधि

5. भारत में निर्धनता रेखा का अनुमान लगाने के लिए समय अवधि के अनुसार निदर्श सर्वेक्षण कौन करता है?

(अ) राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन

(ब) राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण संगठन

(स) निदर्श सर्वेक्षण संगठन

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

6. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराता है?

(अ) 70 (ब) 80

(स) 90 (द) 100

पाठांत प्रश्न

1. भारत में बेरोजगार के क्या कारण हैं?
2. भारत में निर्धनता के कारणों पर वाद-विवाद कीजिए।
3. भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में शुरू किए गए निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए।
4. भारत में प्रदेशीय असमानता की मात्रा की व्याख्या कीजिए।
5. भारत में प्रदेशीय असमानता के क्या कारण हैं?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

4.1

1.4.2 भाग देखिए

2.4.3.2 भाग देखिए

4.2

1. निर्धनता रेखा (देखिए भाग 4.4)
2. देखिए भाग 4.5.4
3. देखिए भाग 4.5.1

4.3

1. (स) 2. (अ) 3. (ब) 4. (द) 5. (ब) 6. (द)